

डॉ० हेमलता डॉ० हिमाल

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड सरकार ।

सोचामें,

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 09 अक्टूबर, 2007

विषय: जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत महारू देवता मंदिर लखरथार का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

सम्बन्धित विषयक आपके पत्र संख्या-385/2-6-449/2006-07, दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में पुरी यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत महारू देवता मंदिर लखरथार का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु० 30.90 लाख (रुपये तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत के आगमनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि वित्तव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व रक्षाम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में वित्तव्ययता गिताना आवश्यक है। व्यय करते समय वित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3-आगमन में उल्लिखित दरों का निरीक्षण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जाँच कर शिक्क आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाग से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन/मानविष्य मंडित कर नियमानुसार रक्षाम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5-कार्य पर उत्तम ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6-एक मुश्त प्राविधान को कर्म करने से पूर्व विस्तृत आगमन मंडित कर नियमानुसार रक्षाम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7-कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य-नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विश्लिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8-कार्य कराने से पूर्व स्थल का भू-माप निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जायें।

9-आगमन में जिन मदों हेतु जो चाँही स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10-निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा बाढ़ व नदी के बहाव आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का परीक्षण निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण से पूर्व कर लिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

12-उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-03-2008 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रगल्भ-पत्र ग्याशीध सारान को उपलब्ध करा दिया जायेगा तदोपरान्त ही अवशेष अथवा दूसरी किरत अवशेष की जायेगी।

13-कार्य प्रारम्भ के समय सम्बन्धित निर्माण एजेंसी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का

अमर, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का चिक्करण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करावेगा एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ अवश्य शासन को तथाशीघ्र उपलब्ध करावेगा।

14-कार्यदायी संस्था का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की ओर निर्गत शासनादेश संख्या-38/XXVII/2007 14 अगस्त, 2007 के अनुसार ही किया जायेगा।

15-योजना पर धनसाक्षि तभी व्यय की जायेगी जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाय तथा राज्य सेक्टर योजनाओं हेतु निर्गत अन्य संगत दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

16-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूर्वनिर्गत परियोजना-80-सामान्य-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कमोनेट प्लान-01-पर्यटन विकास की नई परियोजनाए-24-वृहत निर्माण कार्य के तहत आता जायेगा।

17-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के असाओ 310-463/XXVII(2)/2007, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी राहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ० हेमलता कौंडियाल)  
अपर सचिव।

संख्या- 100 /VI/2007-5(6)2006, टी०सी० तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकूमारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- नरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- निजी सचिव, भा० मुख्यांत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव, भा० पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2,
- 9- श्री एन०एम०पन्त, अपर सचिव वित्त।
- 10- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय भरितर।
- 12- माई फाईल।

आज्ञा से

(डॉ० हेमलता कौंडियाल)  
अपर सचिव।